Sixteenth Loksabha

an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs and Minister of State in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation laid a statement regarding Government Business during the remaining part of the 14th session of the 16th Lok Sabha.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, with your permission, I rise to announce that Government Business during the remaining part of the Session will consist of:-

- Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - (*it contains consideration and passing of (a) the Fugitive Economic Offenders Bill, 2018, (b) the Chit Funds (Amendment) Bill, 2018 and (c) the National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017.)*
- Consideration and passing of the following Bills: -

    (i) The Dentists (Amendment) Bill, 2017.

    (ii) The Negotiable Instruments (Amendment0 Bill, 2017.

    (iii) The Public Premises (Eviction of Un-authorised Occupants) Amendment Bill, 2017.

    (iv) The Consumer Protection Bill, 2018.

(v) The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018.

(vi) The National Sports University Bill, 2017.

(vii) The Major Ports Authorities Bill, 2016.

(viii) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017.

(ix) The Representation of People (Amendment) Bill, 2017.

Consideration and passing of the Constitution (One Hundred and Twenty-Third Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha, as reported by Select Committee of Rajya Sabha and as returned by Rajya Sabha with Amendments. *(...interruptions)*

HON. SPEAKER: Submissions may be laid on the Table of the House.

(…Interruptions)

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह के कार्य सूची में शामिल किया जाए:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर में टाटा कम्पनी है जो शहर के बिल्कुल बीचों-बीच में स्थिति है। यह बड़ी कंपनी होने के कारण प्रतिदिन बड़ी-बड़ी हजारों गाड़ियों का आना-जाना लगा रहता है। इसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग 40 से 50 हजार है, जिसके कारण शहर में जगह-जगह पर ट्रैफिक जाम की समस्या लगा रहता है और प्रतिवर्ष औषतन 400 दुर्घटनायें होती हैं, जिसमें 300 लोगों की मौत होती है। पूरे टाटा शहर में एक भी फ्लाईओवर नहीं होने के कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं। जबकी वहाँ के लोगों की यह माँग वर्षों पुरानी है।

2. चांडिल, बडाम, पटमदा, वॉधवान वाया झाडग्राम तक लगभग 12 करोड़ रुपये के लागत से रेलवे लाइन निर्माण का सर्वे हो चुका है, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसके साथ-साथ चाकुलिया, बहरागोडा, बुडामारा उडिसा तक का सर्वे 10 वर्ष पूर्व हो चुका है, लेकिन अभी तक इस नई रेलवे लाइन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वर्षों से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। टाटा से बादाम पहाड़ होते हुए क्योमझर तक डबल लाइन बनाया जाए।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय अध्यक्ष जी निम्न लोक महत्व के विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल कराने की कृपा करें।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मंदाकिनी नदी का जल स्तर काफी कम हो गया है। कर्वी के आगे बनकट के पास से ही उसमें जल बिल्कुल नहीं रह गया है। जिसके आस-पास के महुवा गाँव तक के सैकड़ों गाँवों में लोगों व पशुओं के लिए जल संकट खड़ा हो गया है। अस्तु इस सदन में चर्चा कराकर निदान के उपाय किए जाँए।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बाँदा एवं चित्रकूट के जिला अस्पतालों व पी.एस.सी. व ग्रामीण अस्पतालों में डाक्टरों एवं तकनीशियनों के अधिकतर पद खाली पड़े हैं। अस्तु लोगों को चिकित्सा के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्तु सभी पदों की यथाशीघ्र पूर्ति करने हेतु इस विषय को सदन में चर्चा कराकर शीघ्र पदों को भरने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए:

1. उत्तर गुजरात के मेहसाणा और पालनपुर रेलवे स्टेशनों से सूरत और मुंबई के लिए समर स्पेशल ट्रेन वीकली का प्रावधान पैसेंजरों के लिए किया जाए।

2. दिव्यांग जनों को बीएसएनएल कनेक्शन से लाभान्वित करने के लिए रेंट फ्री कनेक्शन के जो प्रावधान किए हैं, उसका प्रचार-प्रसार व्यापक तौर पर हो और सीनियर सिटीजनों को बीएसएनएल कनेक्शल के तहत सिर्फ 500 रुपये में कनेक्शन मिलता है, उसका भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

1 मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर एक अत्यंत पिछड़ा एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ सड़क, दूरसंचार सुविधा एवं परिवहन का अभाव है। सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जन-सुविधा के लिए वित्तीय सहायता दी है, जिनमें शिवहर को अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है।

अनुरोध पूर्वक कहना है कि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मोतिहारी से सोनवर्षा भाया ढ़ाका-भंडार-खोड़ीपाकड़-अदौरी- बसंतपट्टी-सीतामढ़ी होते हुए एक नया एन.एच. निर्माण कराए जाने का कार्य।

2 मेरे संसदीय क्षेत्रान्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिला का फेनहारा प्रखण्ड काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। इसके ककरहिया नाला पर पुल का निर्माण हो जाने से फेनहारा एवं पकड़ीदयाल प्रखण्ड के लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा। फेनहारा प्रखण्ड में ककरहिया नाला पर नया पुल निर्माण कराए जाने का कार्य।

श्री राम टहल चौधरी (राँची): अध्यक्ष महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत राँची गेतलसूद डैम एवं इसके दूसरे भाग रुका डैम के आस-पास का क्षेत्र बड़ा ही रमणीय और सुन्दरता से भरपूर है। यहां पर स्थानीय लोग और झारखण्ड से और विदेशी पर्यटक हजारों की संख्या में आते हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन संबंधी सुविधाएं दिलवाने हेतु गेतलसूद डैम एवं इसके दूसरे भाग रुका डैम के आस-पास क्षेत्रों को केन्द्र स्तर पर पर्यटन स्थल स्थापित करने का कार्य करने हेतु।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र राँची में पिछले वर्ष 16 दिसंबर, 2016 को सुबह 03 बजे से 05 बजे के बीच मेरे संसदीय क्षेत्र राँची के बूटी बस्ती की रहने वाली एवं आरटीसी इंजिनियरिंग कालेज की बीटेक छात्रा सुश्री जया भारती के साथ गैंग रेप एवं उसके बाद उसको जला दिया गया था। यह घटना दिल्ली के निर्भया हत्या कांड की याद दिलाती है। इसकी पूरे झारखण्ड में तीव्र भर्त्सना की गई है। पुलिस विभाग एक साल के बाद भी हत्यारों को नहीं पकड़ सकी है। इस गैंग रेप एवं हत्या में पुलिस की नाकामयाबी और उनकी असफल भूमिका एवं प्रभावशाली जाँच का कार्य करने हेतु।

धन्यवाद

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, लोकसभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जायें:-

1. देश के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय होती जा रही है। किसान कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं। क्योंकि उनको फसल से उतनी आमदनी नहीं होती, जितनी उनकी लागत लगती है। जब फसल तैयार होता है , तो रेट आधे हो जाते हैं और लेने वाला कोई नहीं होता। एम.एस.पी. तो सिर्फ कागजी सूचना बनकर रह गई है। शादी-ब्याह, खेती के औजार, ट्रैक्टर आदि खरीद के लिए उन्हें अपने खेतों को गिरवी रखना पड़ता है। अत: सरकार किसानों को विशेष योजना के तहत पूर्ण कर्ज माफ करे और ब्याज-मुक्त ऋण देने का भी प्रावधान करे। साथ ही विशेषकर छोटे और मझोले किसान, जो साहूकारों के कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उन्हें भी आर्थिक मदद दिया जाये।

2. पूरे देश में खेती पर आधारित कृषि-श्रमिकों की दशा बहुत ही खराब है। इनकी संख्या देश् भर में 55 से 58 प्रतिशत है। वैसे ही हमारी खेती मौसम पर आधारित है, जिससे कृषि-श्रमिकों को बराबर रोजगार नहीं मिलता है। विशेषकर महिला कृषि-श्रमिक की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनके छोटे-छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं। कुछ मदद मनरेगा से हो जाया करता था, परंतु अब तो मनरेगा भी सुचारू रूप से नहीं चलता है। क्योंकि सरकार पूरा फण्ड ही नहीं दे रही है। बिहार जैसे गरीब राज्यों की स्थिति तो और ही खराब है। अत: केन्द्र सरकार कृषि-श्रमिकों को पेंशन के तर्ज पर मासिक-भत्ता देने की योजना बनाकर उनके परिवार के निर्वहन की व्यवस्था करे।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के जिला मुख्यालय डालटनगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर सन् 2004 में ही कर दिया गया है, जबकि रेलवे स्टेशन का नाम अभी तक डालटनगंज ही है। इसे मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन किया जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के अंतर्गत संचार व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। पलामू संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले यथा पलामू एवं गढ़वा नक्सल प्रभावित

जिले हैं, तथापि दूरसंचार की व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है। वहां मोबाइल टावर्स की संख्या अत्यंत कम है, इसे बढ़ाने की कृपा की जाए।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए:

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्तमान में अनुसूचित जाति समुदाय 50 प्रतिशत जनसंख्या वाले गांवों में दी जा रही है। जो इन वर्गों के विकास के लिए बहुत ही लाभकारी और फायदेमंद है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में इसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) एवं पिछड़े वर्ग बाहुल्य निवास करने वाले गांवों को भी शामिल कर विकसित करने के लिए भी योजना बनाई जाए।

कृषि विज्ञान केन्द्र छत्तीसगढ़ राज्य सात कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की मांग राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसकी स्वीकृति कि अपेक्षा है। मैं अपने गृह जिला मुंगेली सहित छत्तीसगढ़ में सभी सात नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की मांग करता हूं, जिससे किसानों को लाभान्वित किया जाए।

DR. KARAN SINGH YADAV (ALWAR): The following topics be included for discussions in the list of business of next week:-

1. Need to start ESI Medical College and Hospital in newly constructed buildings at Alwar.
2. Need to bring Chambal waters to Alwar District of Rajasthan.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की कृपा की जाए।

1. वर्ष 2011 में हुए सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (सेक) की आधार मानकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अत्यंत निम्न वर्ग के लोगों की सूची तैयार की गई है जिसके अनुसार लोगों की राशन कार्ड, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत एलजीपी गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास, चिकित्सा अनुदान, वृद्धा एवं विधवा पेंशन सहित केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है ।

2. वर्ष 2011 में हुए सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (सेक) की सूची में कई विसंगतियां भी पाई गयी है । जो वास्तव में गरीब एवं निम्न वर्ग से हैं वैसे लोगों का नाम सूची में नहीं है जिसके कारण सैसे लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है । साथ ही जनगणना के बीते 7 वर्षों में बीपीएल श्रेणी में कई नए परिवार भी जुड़े हैं उन्हें भी यह लाभ नहीं मिल पा रहा है ।